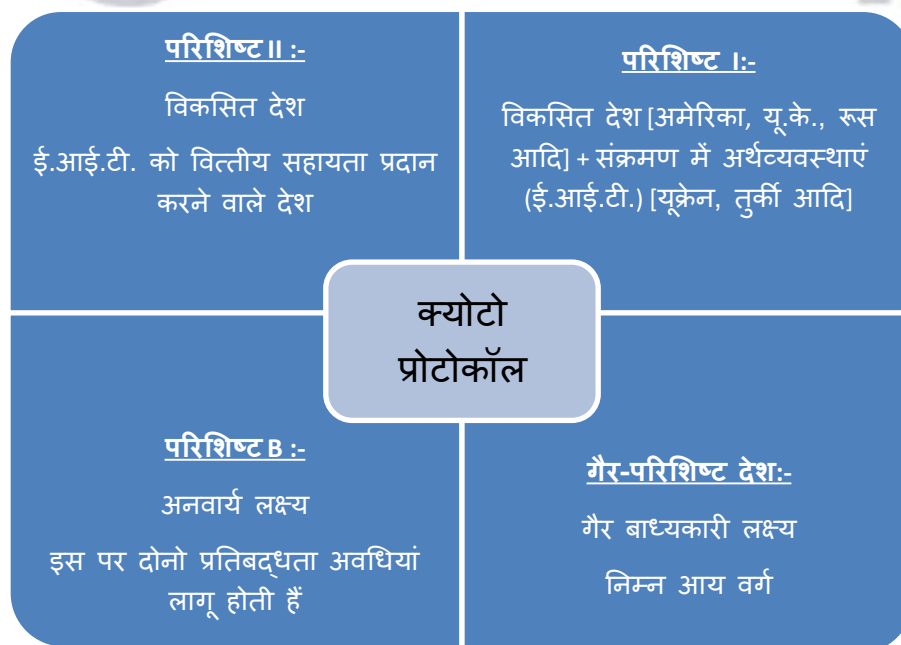


क्योटो और पेरिस समझौता



क्योटो प्रोटोकॉल

- यू.एन.एफ.सी.सी. की बैठकों को सी.ओ.पी. (पार्टियों का सम्मेलन) कहा जाता है।
- क्योटो पर जापान के क्योटो में यू.एन.एफ.सी.सी. के तीसरे सी.ओ.पी. में हस्ताक्षर किए गए थे।
- वर्ष 2005 में प्रोटोकॉल को लागू किया गया था।
- इसमें लगभग 192 सदस्य देश शामिल हैं, जिसमें अमेरिका (प्रोटोकॉल पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए) और कनाडा (2012 में बाहर हो गया) जैसे प्रमुख प्रदूषणकारी देश अनुपस्थित हैं।
- यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो 1992 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) का विस्तार करती है जो राज्य दलों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है।
- परिशिष्ट A में 6 ग्रीनहाउस गैसों: कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂), मीथेन (CH₄), नाइट्रस ऑक्साइड (N₂O), हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC), परफ्लोरोकार्बन (PFC) और सल्फर हेक्साफ्लोराइड (SF₆) सूचीबद्ध हैं।
- क्योटो की पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008-2012 में समाप्त हो गई थी, जिसके बाद दूसरी प्रतिबद्धता अवधि शुरू हुई थी, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल (2013-2020) के लिए दोहा संशोधन के रूप में जाना जाता है।
- क्योटो प्रोटोकॉल ने देशों को निम्नलिखित समूहों में विभाजित किया है, जिन्हें परिशिष्ट कहा जाता है: -



- जो देश क्योटो के लिए बाध्य हैं, वे नीतियों और घरेलू कानूनी अधिनियमों द्वारा घरेलू कार्यों द्वारा अपने कटौती लक्ष्यों को पूरा करने हेतु बाध्य हैं।
- लेकिन वे तीन "मार्केट-आधारित तंत्र" के माध्यम से अपने लक्ष्य का हिस्सा पूरा कर सकते हैं।

क्योटो लचीले बाजार प्रोटोकॉल तंत्र में शामिल हैं:

1. स्वच्छ विकास तंत्र (सी.डी.एम.)
2. उत्सर्जन व्यापार
3. संयुक्त कार्यान्वयन (जे.आई.)

कार्बन क्रेडिट क्या हैं?

अतः यदि हमारे माता-पिता द्वारा उन चीजों पर खर्च करने के लिए एक निश्चित राशि दी जाती है, जिन्हें खरीदने की हमें आवश्यकता होती है। आप जाते हैं और एक ड्रेस, एक प्ले स्टेशन, कुछ गेम खरीदते हैं लेकिन अनुमान लगाते हैं कि आपने उन पर कितना अधिक खर्च कर दिया है और आपके पास कुछ निश्चित "क्रेडिट" में कमी हो जाती है, जो यहां पैसा है, अतः आप अपने दोस्त के पास जाते हैं और एक इकाई क्रेडिट उधार लेते हैं जो आपने दुकान पर भुगतान करके अतिरिक्त खर्च कर दी थी और इसके बदले में आप अपने मित्र को कुछ ऐसा देते हैं जिसकी उसे आवश्यकता होती है। इस प्रकार आप दोनों को वह मिल जाता जिसकी आप दोनों को आवश्यकता होती है।

समान प्रकार से, जब देश विकास की दिशा में खोज करते हैं तो वे उन्हें सौंपे गए कार्बन क्रेडिट का अधिक उपयोग करने की प्रवृत्ति रखते (1 कार्बन क्रेडिट= 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड) हैं। इसलिए वे इन क्रेडिटों को दूसरे देश से खरीदते हैं जिन्होंने क्रेडिट की अपनी निर्धारित राशि का उपयोग नहीं किया है। उदाहरण के लिए, इंडोनेशिया जैसा छोटा देश शायद एक गति से विकसित नहीं हो रहा है और उसके पास अतिरिक्त क्रेडिट है इसलिए इन क्रेडिटों का तब कार्बन बाजारों में "व्यापार" होता है, जो शेयर बाजारों के समान हैं। इसलिए जरूरतमंद देश उन्हें खरीदता है और इससे प्राप्त पैसे का उपयोग बेचने वाले देश में किसी भी विकास गतिविधियों में किया जाता है।

अतः यह दोनों देशों के लिए जीत की स्थिति है!

स्वच्छ विकास तंत्र:-

- विकासशील देशों में उत्सर्जन-कटौती परियोजना को लागू करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल (अनुबंध बी पार्टी) के अंतर्गत एक उत्सर्जन-कमी या उत्सर्जन-सीमा प्रतिबद्धता के साथ एक देश की अनुमति देता है।

उत्सर्जन व्यापार

- यह विकसित देशों के बीच ए.ए.यू. (असाइन्ड अमाउंट यूनिट्स) बेचने और खरीदने की व्यवस्था है।
- इसे पूंजी और व्यापार तंत्र भी कहा जाता है।

संयुक्त कार्यान्वयन (जे.ई.)

- विकासशील देशों में उत्सर्जन-कटौती परियोजना को लागू करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल (अनुबंध बी पार्टी) के अंतर्गत एक उत्सर्जन-कमी या उत्सर्जन-सीमा प्रतिबद्धता के साथ एक देश की अनुमति देता है।

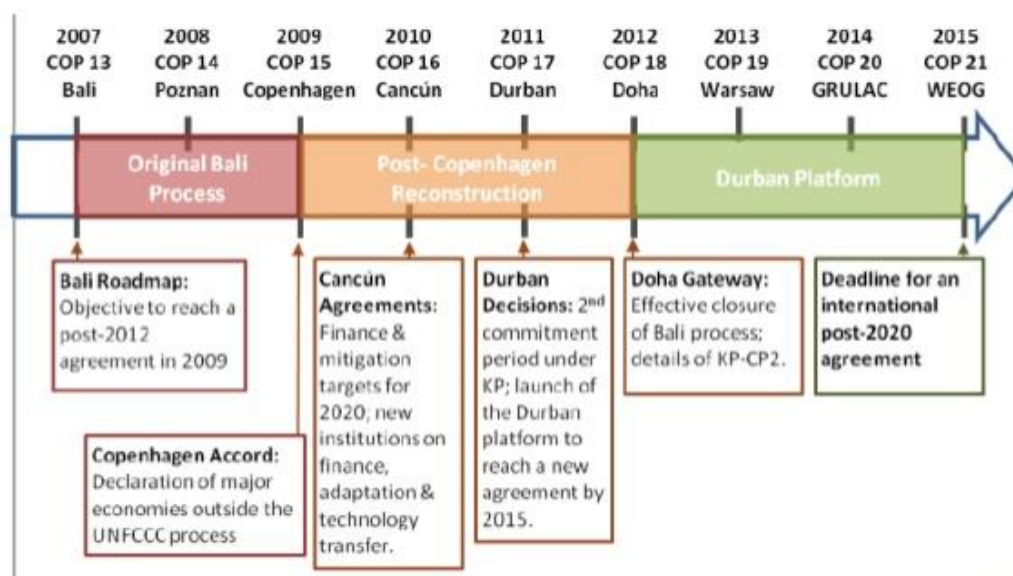
यदि कोई देश क्योटो प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता है?

- यदि कोई भी देश क्योटो तंत्र का अनुपालन नहीं कर रहा है तो देश को संयुक्त कार्यान्वयन के माध्यम से कोई भी क्रेडिट हासिल करने की अनुमति नहीं होती है।
- कार्बन क्रेडिट की अनुमत राशि से अधिक मात्रा पर देश के तीस प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना देने की भी उम्मीद है।

क्योटो के बाद शिखर सम्मेलन

- क्योटो प्रोटोकॉल, जो दो प्रतिबद्धता अवधि में लागू किया गया था, पहली 2008 से 2012 तक और दूसरी प्रतिबद्धता अवधि 2012 से 2020 तक प्रोटोकॉल (2012) में दोहा संशोधन के समाप्त होने के बाद और इसके बाद एक नया प्रोटोकॉल लागू करने की आवश्यकता थी।
- सदस्य राष्ट्रों ने क्रमिक सी.ओ.पी. (पार्टियों का सम्मेलन) के लिए मुलाकात की थी और लीमा में सी.ओ.पी. 20 के दौरान, देशों ने क्योटो में मौजूद विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर को कम करने का फैसला किया था।
- किसी भी विकसित या विकासशील देश पर कानूनी बाध्यता के बिना अपने स्वयं के कटौती लक्ष्य को निर्धारित करने के बारे में चर्चा हुई है।

Since Bali 2007



CAN

विकसित और विकासशील देशों के बीच के मुद्दे:-

- क्योटो प्रोटोकॉल ने सदस्य राष्ट्रों को विभिन्न प्रमुखों में विभाजित किया है:

अनुलग्नक I:- जिसमें विकसित देशों के साथ-साथ संक्रमण में अर्थव्यवस्थाएं (ई.आई.टी.) जैसे कि यूक्रेन, तुर्की और कुछ पूर्वी यूरोपीय देश शामिल हैं।

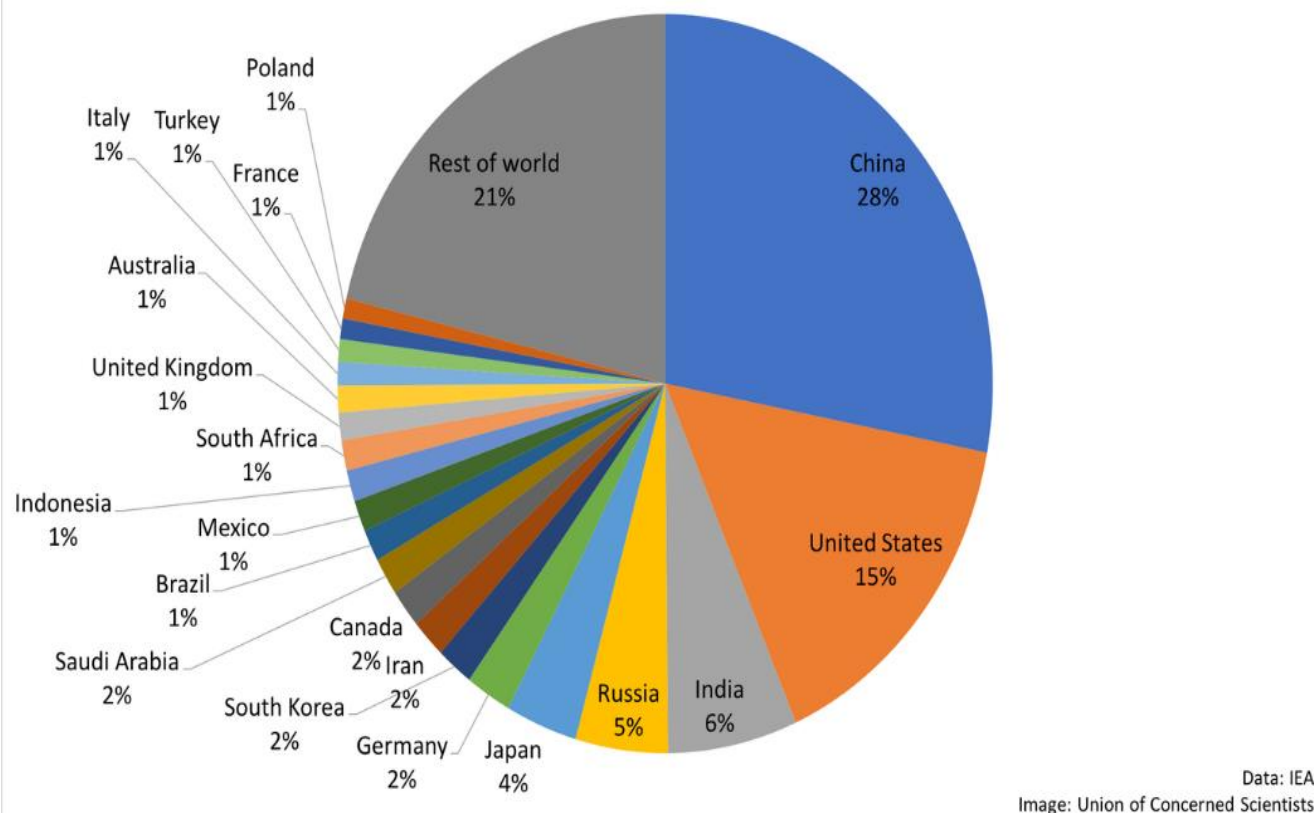
अनुलग्नक II:- इसमें अनुलग्नक I के देशों का एक उपसमूह शामिल है, जिसमें मुख्य रूप से सबसे उन्नत अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जो ओ.ई.सी.डी. के एक भाग का निर्माण करती (आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन) हैं।

गैर अनुलग्नक देश:- सबसे कम विकसित देश हैं।

- विकसित देश, कम विकसित देशों और विकासशील देशों पर उनके तेजी से औद्योगिकीकरण के कारण बढ़ते ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का आरोप लगाते रहे हैं।
- वे कहते हैं कि लंबे समय से भारत और चीन जैसे देशों को "कानूनी रूप से गैर-बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं" प्रमुखों के अंतर्गत नहीं रखा गया है और वे लंबे समय से पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं।

- भारत, सी.बी.डी.आर. (सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारी) के क्योटो के मुख्य सिद्धांत के बारे में अपनी स्थिति में निरंतर बना रहा है।
- उनके अनुसार उनकी विकास की आवश्यकताएं अभी भी बढ़ रही हैं और बड़ी संख्या में आबादी गरीबी, भुखमरी और अन्य मानव विकास के मुद्दों से पीड़ित है।

Share of global carbon dioxide emissions from fuel combustion (2015)



पेरिस शिखर सम्मेलन के लिए पूर्व कर्सर: -

लीमा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (2014) सी.ओ.पी.- 20, सी.एम.पी.- 10)

- इस शिखर सम्मेलन का समग्र उद्देश्य वर्ष 2030 तक वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1850 आधार रेखा या पूर्व-औद्योगिक युग से अधिक 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना था।
- समझौता चाहता था कि पार्टियां आई.एन.डी.सी. के नाम से जानी जाने वाले पेरिस शिखर सम्मेलन में अपने राष्ट्रीय रूप से निर्धारित लक्ष्यों को बाद में ग्रहण कर ले।
- शिखर सम्मेलन बिना किसी ठोस निर्णय के समाप्त हो गया था।

पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन

- पेरिस जलवायु शिखर सम्मेलन, हाल के दिनों का सबसे महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन है। इसे क्योटो के बाद का सबसे निर्णायक समझौता माना जाता था।
- राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित प्रतिबद्धताओं (आई.एन.डी.सी.) के कारण इसका विशेष महत्व है जो सदस्य देशों द्वारा अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करने के लिए व्यक्तिगत प्रतिज्ञा हैं।
- पेरिस समझौते के अंतर्गत प्रत्येक देश को जी.एच.जी. को सीमित करने के लिए किए गए योगदान की योजना, निर्धारण और नियमित रूप से रिपोर्ट करना चाहिए। इसने पहली बार "बॉटम अप" दृष्टिकोण का अनुसरण किया है।

THE PARIS CLIMATE AGREEMENT: KEY POINTS

The landmark pact enters into force on Friday and is to be implemented by 196 countries

Temperatures
2100



- Keep warming "well below 2 degrees Celsius". Continue all efforts to limit the rise in temperatures to 1.5 degrees Celsius

Finance
2020-2025



- Rich countries must provide 100 billion dollars from 2020, as a "floor"
- Amount to be updated by 2025

Differentiation



- Developed countries must continue to "take the lead" in the reduction of greenhouse gases
- Developing nations are encouraged to "enhance their efforts" and move over time to cuts

Emissions objectives
2050



- Aim for greenhouse gases emissions to peak "as soon as possible"
- From 2050: rapid reductions to achieve a balance between emissions from human activity and the amount that can be captured by "sinks"

Burden-sharing



- Developed countries must provide financial resources to help developing countries
- Other countries are invited to provide support on a voluntary basis

Review mechanism
2025



- A review every five years. First mandatory world review: 2025
- Each review will show an improvement compared with the previous period

Climate damage



- Vulnerable countries have won recognition of the need for "averting, minimising and addressing" losses suffered due to climate change

AFP

पेरिस शिखर सम्मेलन के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत ये प्रमुख उद्देश्य हैं:-

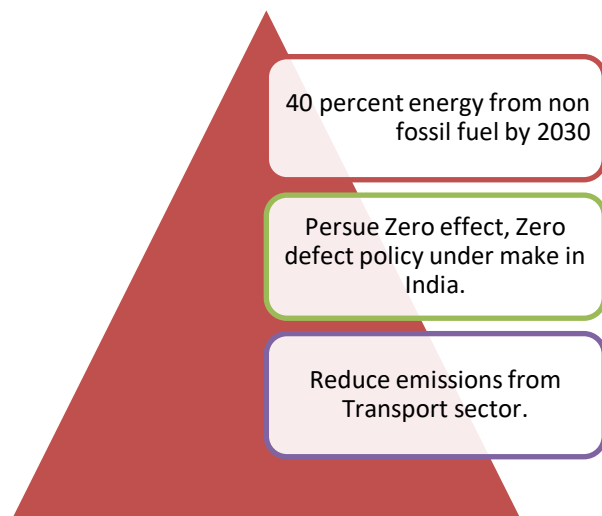
- पूर्व-औद्योगिक स्तरों से अधिक 2 ° C से कम तक वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को रोकना और इसके साथ ही तापमान में वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5 ° C अधिक

- तक सीमित करने के प्रयासों का अनुसरण करना, जिसका अनुसरण करके जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित किया जा सकता है।
- ii. निम्न ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की दिशा में एक मार्ग के साथ वित्त प्रवाह को निरंतर बनाए रखना और उपयुक्त वित्तपोषण तंत्र खोजना
- वर्ष 2020 से 100 बिलियन डॉलर का कोष बनाया जाना है, जिसकी समीक्षा वर्ष 2025 तक की जानी है।
 - विकासशील देशों को "अपने प्रयासों को बढ़ाने" के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और समय के साथ अपनी कटौती को बढ़ाने के लिए एक ही समय में विकसित देशों को आगे बढ़ना जारी रखना चाहिए।
 - समीक्षा तंत्र प्रत्येक पांच वर्ष में आयोजित किया जाएगा। सबसे पहले 2023 में आयोजित किया जाएगा।
 - शिखर सम्मेलन, नवंबर, 2016 में 55 देशों द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद प्रभाव में आया था, जो पहले प्राप्त किए गए वैश्विक उत्सर्जन के कम से कम 55% हेतु जिम्मेदार था।
 - 2019 तक, 195 देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और 180 से अधिक देशों ने इसकी पुष्टि की है। भारत ने 2016 में हस्ताक्षर किए थे और पुष्टि की थी।
 - भारत, चीन और यूरोपीय संघ द्वारा सहमत की गई प्रतिबद्धता अवधि दस वर्ष है, जबकि अमेरिका का मत तेज प्रगति के लिए प्रतिबद्धता की अवधि को कम करके पांच वर्ष करना है।



भारत की प्रतिबद्धताएं/ राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित प्रतिबद्धताएं (आई.एन.डी.सी.)

- भारत ने लीमा सम्मेलन के दौरान 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन की तीव्रता को 33 से 35 प्रतिशत तक कम करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है: -



कुछ पहले जिन्हें भारत ने अपनी घरेलू नीतियों में शामिल कर रही है, वे निम्नवत हैं: -

- i. 175 गीगावॉट का सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा स्थापित करें
- ii. वर्ष 2032 तक 63 गीगावॉट की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करना
- iii. "ग्रीन इंडिया मिशन" का पूर्ण कार्यान्वयन
- iv. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एकीकृत तटीय क्षेत्र, जलवायु लचीली कृषि जैसे मिशनों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने राष्ट्रीय राजमार्ग मिशन के अंतर्गत राजमार्ग के दोनों किनारों पर 14,00,000 किलोमीटर लंबी पेड़ों की लाइन विकसित करें।

राष्ट्रीय अनुकूलन कोष

यह 100 करोड़ का हरित ऊर्जा कोष स्थापित है। जो पैसा कोयला उपकर द्वारा एकत्र किया जाता है, वो इसमें जमा किया जाएगा। इस कोष का प्रबंधन राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किया जाना है।

इसे एन.आई.ई. (राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई) के रूप में नियुक्त किया गया है।

पेरिस शिखर सम्मेलन के बाद क्या कार्यप्रणाली होगी?

माराकेच (मोरक्को) जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2016 (सी.ओ.पी.22, सी.एम.पी.12, सी.एम.ए.1)

- पेरिस के बाद पहली बैठक को सी.एम.ए.-1 कहा जाता है जो मोरक्को में आयोजित की गई थी।

www.gradeup.co

इस सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के संदर्भ में योजनाओं पर चर्चा करना और उन्हें लागू करना था और दुनिया को यह दिखाना था कि पेरिस समझौते का कार्यान्वयन चल रहा है।

सी.ओ.पी.22 को "एक्शन सी.ओ.पी." या "कृषि सी.ओ.पी." कहा जाता था।

आने वाली सी.ओ.पी.:

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) या सी.ओ.पी.25 में पार्टियों के सम्मेलन का 25वां संस्करण मैड्रिड (स्पेन) में 2 दिसंबर से शुरू हो गया है।

इस सम्मेलन का उद्देश्य 2015 पेरिस समझौते के लिए नियम-पुस्तिका का पूरा करना है जो 2020 में प्रभावी होंगे।

यह 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल को प्रतिस्थापित करेगा, जो 2020 में समाप्त हो जाएगा।

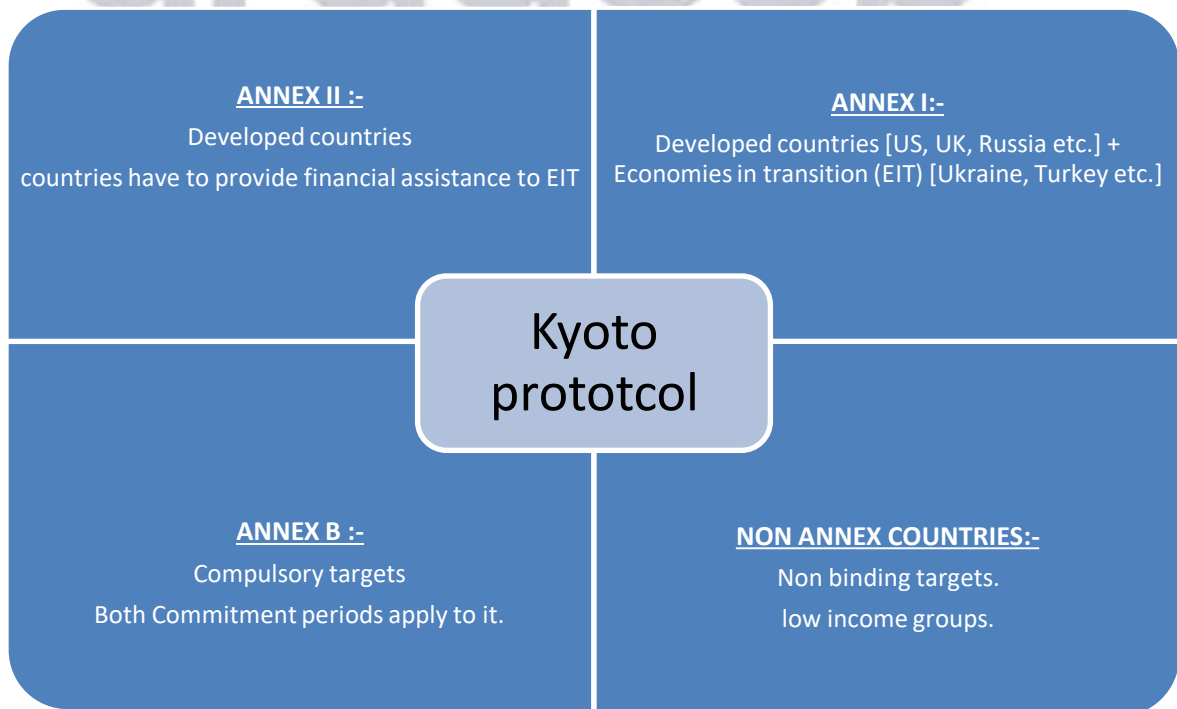
नए कार्बन बाजारों के निर्माण, उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य, देश के व्यक्तिगत लक्ष्य आदि जैसे मुद्दे कैटोवाइस (पोलैंड) 2019 में सी.ओ.पी.24 के दौरान अनसुलझे रहे थे।

इस प्रकार, पेरिस समझौते के अंतर्गत नियम पुस्तिका को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है।

gradeup

Kyoto Protocol

- The UNFCCC meetings are called as COP (Conference of parties).
- Kyoto was signed at the 3rd CoP of the UNFCCC in Kyoto, Japan
- The protocol came into effect in 2005
- There are around 192 member countries where the major polluting countries like US (never signed the protocol) and Canada (withdrew in 2012) are absent.
- It is an international treaty which extends the 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) that commits state parties to reduce greenhouse gas emissions.
- The six greenhouse gases listed in Annex A: **Carbon dioxide (CO₂)**, **Methane (CH₄)**, **Nitrous oxide (N₂O)**, **Hydrofluorocarbons (HFCs)**, **Perfluorocarbons (PFCs)**, and **Sulphur hexafluoride (SF₆)**
- The first commitment period of Kyoto ended in 2012 (2008- 2012), post which the second commitment period started called as the Doha amendment to the Kyoto Protocol (2013 - 2020)
- The Kyoto protocol divides countries into following groups called as annexes: -



- The countries that are bound to Kyoto are bound to meet their reduction targets by domestic actions by the policies and domestic legal acts.
- But they can meet part of their targets through three “**Market-based mechanisms**”.

The Kyoto Flexible Market Protocol mechanisms include:

1. **Clean Development Mechanism (CDM)**
2. **Emission Trading**
3. **Joint Implementation (JI)**

What are Carbon credits?

So, if we are given a certain sum by our parents to spend on things we need to buy. You go and buy a dress, a Play station, few games but guess what you over spend them and you are short of certain “credits” which here is money. So, you go to your friend and borrow 1 unit of credit which you overspend to pay to the shop and in exchange you give your friend something which he needs. This way you both got what you required .

Similarly, when the countries in their quest towards development they tend to over utilise the carbon credits assigned to them, say (1 carbon credit = 1 tonne of Carbon dioxide). So they buy these credits from another country who haven't utilised their assigned amount of credits. For example, a small country like Indonesia might not be developing at a pace and has spare credits so these credits are then “traded” in the carbon markets which are similar to the stock markets. So the country in need buys them and the money is utilised in any development activities in the selling country.

So, it's a win- win situation for both !

Clean development mechanism:-	Emission trading	Joint Implementation (JE)
<ul style="list-style-type: none">allows a country with an emission-reduction or emission-limitation commitment under the Kyoto Protocol (Annex B Party) to implement an emission-reduction project in developing countries.	<ul style="list-style-type: none">It is an arrangement to sell and buy AAU (assigned amount units) among the developed countries.It is also called as Cap and trade mechanism.	<ul style="list-style-type: none">allows a country with an emission-reduction or emission-limitation commitment under the Kyoto Protocol (Annex B Party) to implement an emission-reduction project in developing countries.

If a country do not comply with the Kyoto Protocol?

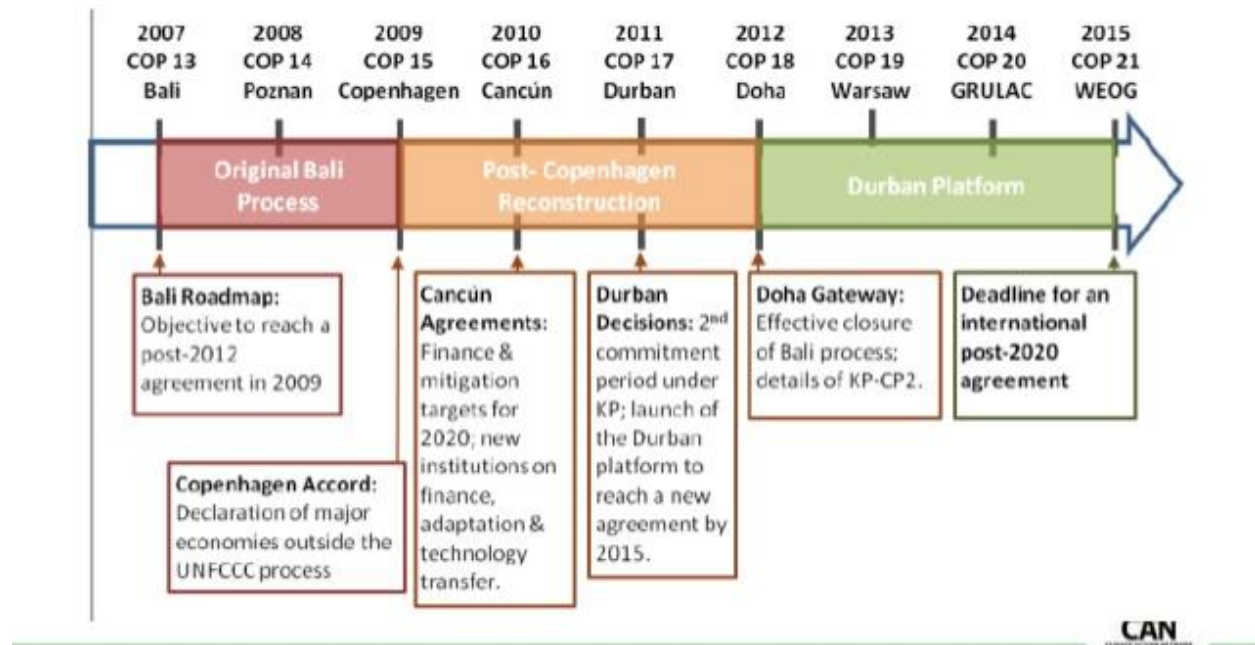
- If any country is not complying with the Kyoto mechanisms than the country is not allowed to gain any credit through joint implementation.
- The country is also expected to pay a penalty of additional thirty percent over the difference by which it exceeded the allowed amount of carbon credits.

Summits post Kyoto

- The Kyoto protocol which was implemented in two commitment periods i.e. the first from 2008 to 2012 and the second commitment period from 2012 to 2020 after the Doha amendment to the protocol (2012) was coming to end and a new protocol was needed to be placed post that.
- The member nations met for successive COP (Conference of parties) and during COP 20 in Lima, the countries decided to wedge the gap between the developed and the developing countries that existed in Kyoto.

- There were discussions about the countries pledging their own reduction targets without any legal binding on any of the developed or developing countries.

Since Bali 2007



Issues between the developed and the developing nations:-

- The Kyoto protocol divided the member nations into various heads like

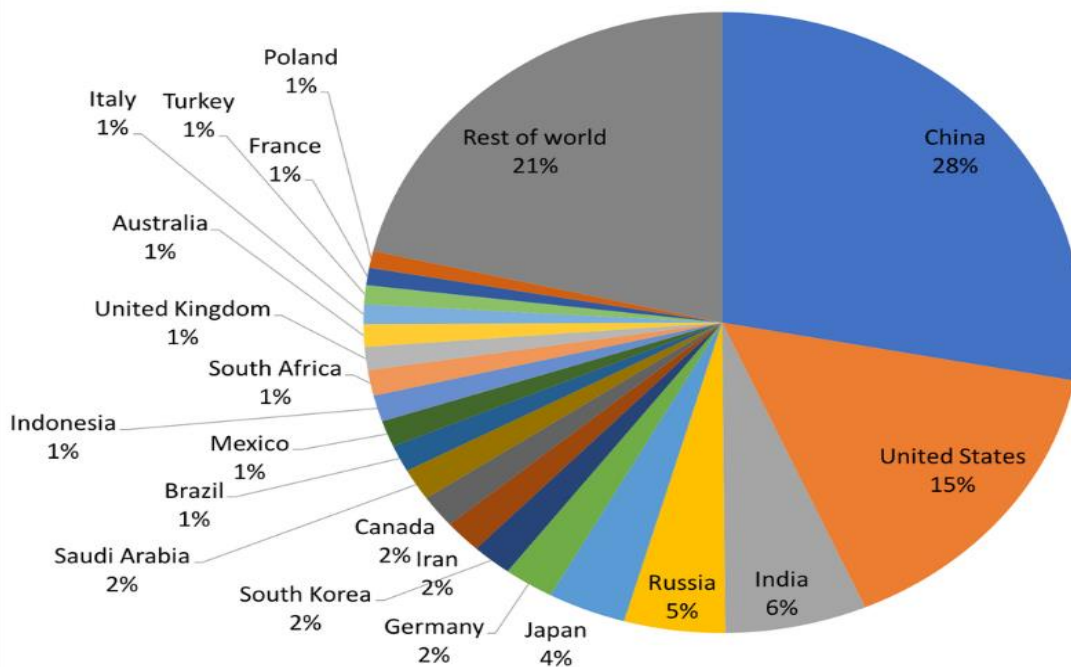
Annex I :- Which comprised of the developed countries along with the economies in transition (EIT's) like Ukrain, Turkey and some east European countries.

Annex II :- This contains a subset of the annex I countries, consisting mainly of the most advanced economies which form a part of OECD (Organisation for economic coperation and development)

Non annex countries :- The least developed countries.

- The developed countries have been accusing the lesser developed nations and developing countries about their rising green house gases emissions due to their rapid industrialisation.
- They say its been long time that countries like India and china are put under “ no legally binding commitments “ head and they have been polluting the environment for a long time now.
- India has been consistent in its position about the core principal of the Kyoto of the **CBDR** (**Common but differentiated responsibility**).
- As per them their development needs are still growing and have a large number of population suffering from poverty, hunger and other human development issues.

Share of global carbon dioxide emissions from fuel combustion (2015)



Data: IEA
Image: Union of Concerned Scientists

Pre Cursor to Paris Summit :-

LIMA CLIMATE CHANGE CONFERENCE (2014) COP- 20, CMP - 10)

- The overall objective of this summit was to limit the global temperature increase by 2030 to 2 degrees Celsius above 1850 baseline or Pre-Industrial era.

- The agreement wanted parties to take up their nationally determined targets later known as INDC's which are the nationally determined targets before the Paris summit.
- The summit ended with no substantial decision.

PARIS CLIMATE SUMMIT

- Paris climate summit is one of the most important summits of recent times. It was supposed to be the most conclusive agreement post Kyoto.
- This has special importance because of the Intended Nationally determined Commitments (INDC's) which are individual pledges by the member nations to limit their greenhouse gas emissions.
- Under the Paris agreement each country must plan, determine and regularly report the contribution it is undertaking to limit the GHG's. It followed the "Bottom up" approach for the first time.

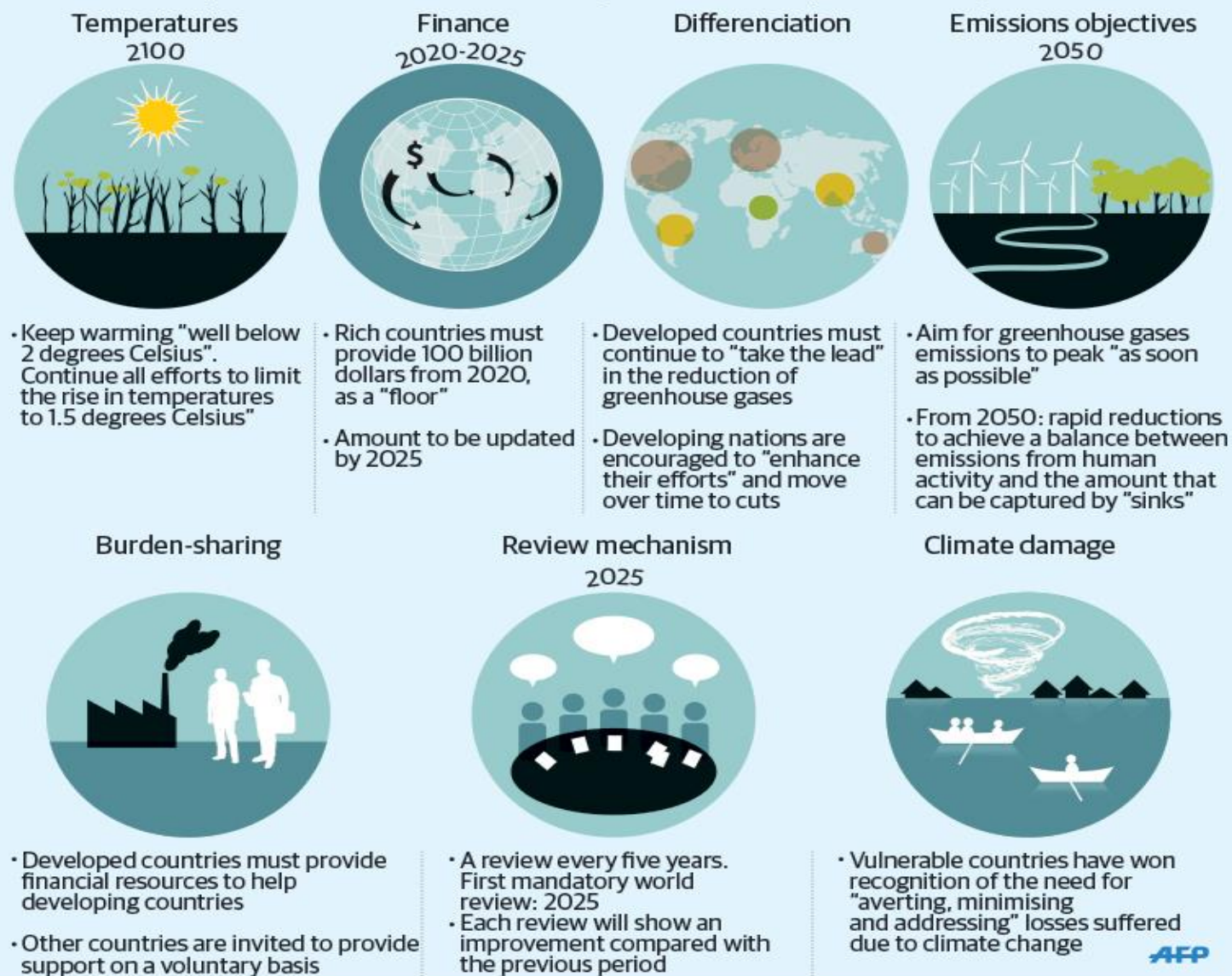
Under the Article 2 of the Paris summit these are the major aims :-

- i) Holding the increase in the global average temperature to well below 2 °C above pre-industrial levels and at the same time pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C above pre-industrial levels, following which the climate change could be controlled.
 - ii) Making finance flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions and to find suitable funding mechanisms
- A 100-billion-dollar fund is to be created from 2020, which is to be reviewed by the year 2025.
 - Developing countries must be encouraged to "enhance their efforts" and move over time to increase their cuts at the same time developed countries continuing to take the lead.





- The reviewing mechanism will be held every five years. First to be conducted in 2023

THE PARIS CLIMATE AGREEMENT: KEY POINTS

The landmark pact enters into force on Friday and is to be implemented by 196 countries

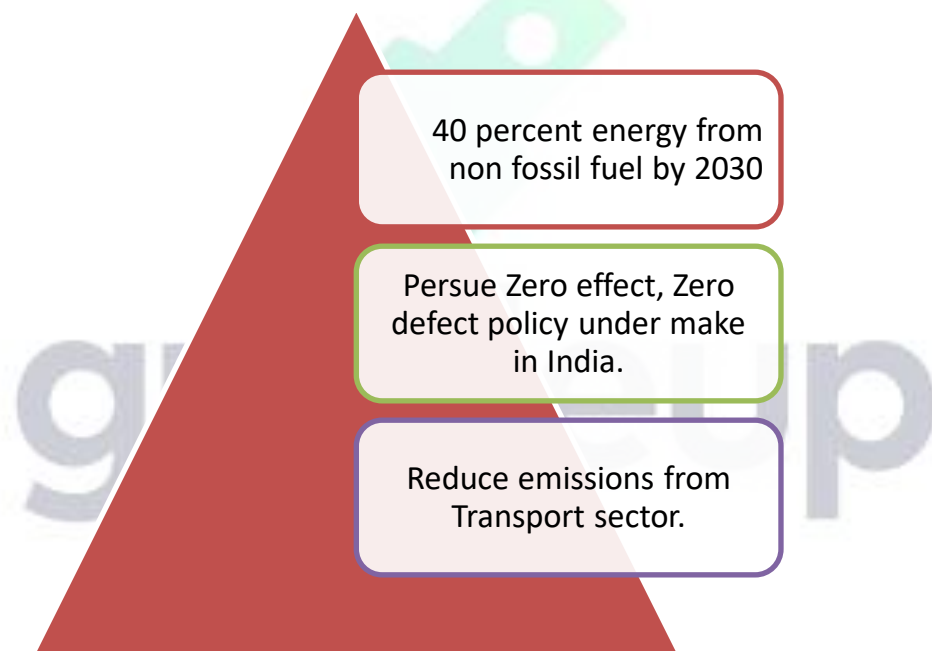


- The summit entered into force in November 2016 after being ratified by 55 countries that account for at least 55% of global emissions had been met.
- As of 2019 ,195 countries have signed the agreement and more than 180 countries have ratified it. India signed and ratified in 2016.
- The commitment period agreed by India, China and the European Union is of ten years, whereas the US is of the view to reduce the commitment period to five years for a quicker progress.

TARGETS FOR PARIS AGREEMENT			
			
INDIA Emission intensity of GDP 33–35% below 2005 levels by 2030, Power capacity to be 40% non fossil fuel based Source: uefcc.int	CHINA Emission intensity of GDP 60–65% below 2005 levels by 2030. Peak emissions around 2030. Non-fossil fuel to be 20% of primary energy consumption by 2030	USA Absolute emissions 26–28% below 2005 levels by 2025	EU (28) Absolute emissions 40% below 1990 levels by 2030

India's Commitments / Intended nationally determined commitments (INDC's)

- India during the Lima conference committed to reduce emission intensity by 33 to 35 per cent by 2030 compared to 2005 levels by: -



Some of the initiatives India plan to take in its domestic policies are as follows :-

- Install a 175 GW of solar energy, Wind energy and geothermal energy
- To fully utilise the installed nuclear energy capacity of 63 GW by 2032
- Full implementation of the “Green India Mission”

- iv) Focus on missions like national clean Ganga mission, national health mission, integrated coastal zones, climate resilient agriculture and develop 14,00,000 km of tree line across both sides of the highway under its national Highway mission.

NATIONAL ADAPTATION FUND

It is a 100 crore green energy fund to be set up. Money which is collected by the coal cess will be deposited in it. The fund is to be managed by the National bank for agriculture and rural development (NABARD).

It has been appointed as the NIE (National implementation entity)

What will be the course after Paris Summit?

Marrakech (Morocco) Climate Change Conference 2016 (COP22; CMP12; CMA1)

- The first meeting post Paris is called as CMA-1 which was held in Morocco.

The purpose of the conference was to discuss and implement plans about combatting climate change and to show to the world that the implementation of the Paris Agreement is underway.

COP22 was called as “Action COP” or “Agriculture COP”.

UPCOMING COP'S:

The 25th edition of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) or COP25 has begun from December 2 in Madrid (Spain).

The aim of the conference is the completion of the rule-book to the 2015 Paris Agreement that will become effective in 2020.

www.gradeup.co

It will replace the 1997 Kyoto Protocol which will end in 2020.

The issues like the creation of new carbon markets, emission reduction targets, country's individual targets, etc. remained unresolved during COP24 at Katowice (Poland) 2019.

Thus, the rulebook under the Paris Agreement could not be finalized.

